I.G.N.O.U. *Based*

NEERAJ®

E.P.S.-15

दक्षिण एशिया : अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति

(South Asia: Economy, Society and Politics)

By: Dr. Naveen Mishra Ph.D (Pol. Science)

Question Bank** Cum **Chapterwise Reference Book

Including **Many Solved Question Papers**

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

Sales Office:
1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi - 6
Ph.: 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501
E-mail: info@neerajignoubooks.com
Website: www.neerajignoubooks.com

MRP ` 200/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

Sales Office : **1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110006**
E-mail: **info@neerajignoubooks.com**
Website: **www.neerajignoubooks.com**

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only	Typesetting by: Competent Computers	Printed at: Novelty Printer

Notes:

1. For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.
3. The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.
4. Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.
5. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
6. If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.
7. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
8. Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its contents, distribution of marks and their level of difficulty.
9. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
10. Subject to Delhi Jurisdiction only.

© Reserved with the Publishers only.

Spl. Note: ***This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.***

How to get Books by Post (V.P.P.)?

*If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website **www.neerajignoubooks.com**. You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).*
*To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website **www.neerajignoubooks.com.***
No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.
We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006

Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: **info@neerajignoubooks.com** *Website:* **www.neerajignoubooks.com**

CONTENTS

दक्षिण एशिया : अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति
(South Asia: Economy, Society and Politics)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-5
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1-4
Question Paper—December, 2017 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1-3
Question Paper—December, 2016 (Solved)	1-4
Question Paper—June, 2016 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2015 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2015 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2014 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2013 (Solved)	1
Question Paper—June, 2012 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2011 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2010 (Solved)	1-2

S.No.	*Chapterwise Reference Book*	*Page*

दक्षिण एशिया : क्षेत्रीय स्वरूप

1. दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता-संग्राम — 1
2. मानव विकास का पार्श्व-चित्र — 6

राज्य की रूपरेखा : भारत

3. भारत : विश्व सत्ता ढाँचे में — 11
4. विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत — 15
5. भारत और उसके पड़ोसी — 20

S.No.	Chapter	Page
	राज्य की रूपरेखा : पाकिस्तान	
6.	पाकिस्तान की राजनीति की संरचनाएँ एवं प्रक्रियाएँ	23
7.	पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एवं समाज	27
8.	पाकिस्तान में सैनिक शासन एवं राजनीति	29
	राज्य की रूपरेखा : बंगलादेश	
9.	बंगलादेश में राजनीतिक संरचना एवं प्रक्रियाएँ	32
10.	बंगलादेश की अर्थव्यवस्था एवं समाज	37
	देश जीवन–परिचय : नेपाल, भूटान	
11.	नेपाल में राजनीतिक आधार एवं प्रक्रियाएँ	42
12.	नेपाल में अर्थव्यवस्था और समाज	47
13.	भूटान : अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति	52
	राज्य की रूपरेखा : श्रीलंका, मालदीव	
14.	श्रीलंका में राजनीतिक संरचनाएँ तथा प्रक्रियाएँ	57
15.	श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और समाज	60
16.	श्रीलंका की राजनीति में जातीयता का समावेशन	64
17.	मालदीव की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति	68
	दक्षिण एशिया में लोकतंत्र	
18.	मानवाधिकार	72
19.	नागरिक समाज	76
20.	दक्षिण एशिया में बहुवाद नियंत्रण के समक्ष चुनौतियाँ	80

S.No.	Chapter	Page
	भूमंडलीकृत होती दुनिया में दक्षिण एशिया	
21.	उदारीकरण और संरचनात्मक समंजन कार्यक्रम	84
22.	भूमंडलीकरण और राज्य	90
	क्षेत्रीय संगठन	
23.	गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास	95
24.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ	98
	क्षेत्रीय सुरक्षा	
25.	दक्षिण एशियाई सुरक्षा	102
26.	आणविक मुद्दे	106
27.	संघर्ष, समाधान और प्रबंधन	110

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

(June – 2019)

(Solved)

दक्षिण एशिया : अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

***नोट :** (i) भाग-I–किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (ii) भाग-II–किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (iii) भाग-III–प्रश्न संख्या 13 के किन्हीं **दो** भागों के उत्तर दीजिए।*

भाग–I

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

प्रश्न 1. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं और संरचनात्मक बदलावों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-27, 'परिचय', प्रश्न 2, पृष्ठ-28, प्रश्न 3, अध्याय-21, पृष्ठ-88, प्रश्न 1

प्रश्न 2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों और उदारीकरण के प्रभावों का आकलन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-21, पृष्ठ-87, प्रश्न 2, 3

प्रश्न 3. बहुलवाद की चुनौतियों का दक्षिण एशियाई देश कैसे संचालन कर रहे हैं, वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-20, पृष्ठ-81, प्रश्न 2, पृष्ठ-82, प्रश्न 1, 2

प्रश्न 4. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की मुख्य चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-24, पृष्ठ-100, प्रश्न 1

भाग–II

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

प्रश्न 5. पाकिस्तान की राजनीति में इस्लाम की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–1990 के दशक के मध्य के वर्षों में पाकिस्तान का संजातीय संघटन कम से कम बड़े समूहों से जनसंख्या के लगभग भाषायी वितरण के अनुरूप ही था। 59.1% पाकिस्तानी स्वयं को पंजाबी 12.1% सिंधी, 7.7% मुहाजिर, 4.3% बलूच तथा 3 प्रतिशत अन्य संजातीय समूहों के सदस्य मानते हैं। प्रत्येक समूह अपनी गृहक्षेत्र पर प्राथमिक रूप से ध्यान केन्द्रित करता है, जैसे–अधिकांश मुहाजिर शहरी सिंध के क्षेत्र में रहते हैं।

अधिकांश पंजाबी समूहों का संबंध इस्लाम से पहले जाट तथा राजपूत जातियों से है। अन्य पंजाबी अरब, फारस, ब्लूचिस्तान, अफगानिस्तान तथा कश्मीर से हैं। इस प्रकार पंजाबी का अलग-अलग उद्भव है, तथापि इन समूहों ने सामंजस्यपूर्ण संजातीय समूह का रूप लिया है, जिसने कृषि तथा रक्षा पर ऐतिहासिक रूप से आधिपत्य स्थापित किया है।

पंजाबी सेना तथा सिविल सेवा के उच्च पदों पर आसीन हैं तथा अधिकांशत: केन्द्रीय सरकार को चलाने में उनका योगदान है। इस स्थिति का कई पुखतु तथा बलूच और विशेषकर सिंधी समुदायों ने विरोध किया है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व मिला है

ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान पंजाब के दक्षिण में स्थित सिंध बम्बई का उपेक्षित भीतरी प्रदेश था। प्रमुख जमीदारों (बाडेरा) के छोटे समूह का यह समाज था। शोषित काश्तकार किसानों, जिनकी संख्या अधिक थी, को दासता झेलनी पड़ती थी। स्वतंत्रता के समय इस प्रान्त में धन तथा निर्धनता के दो छोर विद्यमान थे।

विभाजन के बाद के वर्षों में लाखों हिन्दू तथा सिक्ख सिंध से भारत चले गए और उनके स्थान पर लगभग 70 लाख मुहाजिर आ गए, जिन्होंने प्रान्त के व्यावसायिक जीवन में सुशिक्षित हिन्दुओं तथा सिक्खों की जगह ले ली। बाद में मुहाजिरों ने शरणार्थ जन आंदोलन (मुहाजिर कौमी महज-एम क्यू एम) को राजनीतिक आधार उपलब्ध कराया। जैसे-जैसे कराची की मुहाजिर शहर के रूप में पहचान बनी, तो सिंध के अन्य शहर–थट्टा, हैदराबाद तथा लरकाना, सिंधी विरोध के मुख्यालय बन गए।

उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त की पहचान विश्व के सबसे बड़े जनजातीय समूह, पश्तुन के रूप में की जाती है। वे

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

ब्लूचिस्तान तथा दक्षिण अफगानिस्तान का प्रमुख समूह है। भारतीय उप-महाद्वीप से अंग्रेजों के जाने के समय पर फ्रंटीयर कांग्रेस, जोकि खान अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता में अत्यंत सक्रिय थी, ने पश्तुनिस्तान के अलग राज्य के गठन की मांग की। यह मांग न माने जाने पर यह क्षेत्र पाकिस्तानी राज्य का हिस्सा बना, परंतु इसने पश्तुन आंदोलन की नींव रखी।

1980 के दशक से कई पश्तुन पुलिस, सिविल सेवा तथा सेना में शामिल हुए हैं तथा देश के यातायात नेटवर्क पर इनका आधिपत्य है। उन्हें पाकिस्तान की राजनीतिक संरचना में प्रतिनिधित्व भी मिला है, जिससे कुछ हद तक पश्तुन आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है।

पाकिस्तान के लगभग 97% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें से 77% सुन्नी तथा 20% शिया हैं, जबकि अन्य 3% जनसंख्या बराबर रूप से ईसाई तथा अन्य धर्मों की है।

दक्षिण एशियाई उप-महाद्वीप में इस्लाम का प्रादुर्भाव आठवीं शताब्दी में धुमक्कड़ सूफी साधुओं-पीरों के आगमन के साथ हुआ। जिन क्षेत्रों में इस्लाम सूफियों द्वारा लगाया गया, वहां पर भी इस्लाम काफी हद तक इस्लाम पूर्व के प्रभावों के साथ मिश्रित हो गया। जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसे धर्म का उदय हुआ जो अरब विश्व की तुलना में परम्परागत दृष्टि से अधिक लचीला था।

मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की संविधान सभा के अपने प्रारम्भिक भाषण में धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्धता की बात कहीं, परन्तु मुस्लिम बहुल राज्य के इस परिप्रेक्ष्य में, जिसमें विकास में धार्मिक, अल्पसंख्यकों की बराबर की हिस्सेदारी होगी, इस पर स्वतंत्रता के बाद ही सवालिया निशान लग गए। 1970 के दशक तक भी चर्चा जारी रही–अहमदियों के अधिकारों, धार्मिक सम्बद्धता दर्शाने वाले पहचान पत्र जारी करना तथा इस्लाम को व्यक्तिगत स्तर पर अपनाने में सरकार के हस्तक्षेप पर विवाद चलता रहा।

संयोग से यह अवधि जनरल जिया-उल-हक के सैनिक शासन की भी थी जिसने राजनीतिक स्थिरता की पुनर्स्थापना, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा समाज के इस्लामीकरण के उद्देश्य से सत्ता अपने हाथ में ली।

1970 के दशक के बिल्कुल विपरीत 1980 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान विकास नीतियों को बदला गया। इस अवधि में अस्थिरता लाने वाले बाह्य कारणों की कमी रही। परिणामस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत से अधिक रही। औद्योगिक क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर भुट्टों के शासनकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में हुए निवेश, विशेषकर भारी उद्योगों में हुए निवेश तथा घरेलू मांग में तीव्रता से आई वृद्धि के कारण हुई।

1979 में अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के कारण अंतरर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर्दे पर पाकिस्तान दृष्टिगोचर हुआ, जिससे न केवल उसके शासन को राजनीतिक वैधता मिली अपितु पर्याप्त विदेशी सहायता और युद्ध संबंधी सहायता के साथ-साथ मुद्रा का बहाव देश में होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। अफगान युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा कि सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 20-30% के अनुपात पर अनुमानित समानान्तर तथा अवैध अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया।

1980 के दशक में पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हुई, जो लगभग दशक के अधिकांश समय में लगभग 3 बिलियन डालर प्रतिवर्ष थी। यह राशि सकल घरेलू उत्पाद का 10% तथा चालू लेखा प्राप्तियों का 45% थी। बाहर से प्राप्त राशि के कारण घरेलू आय में वृद्धि हुई और निवेश के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण निजी क्षेत्र में निवेश किया गया।

फिर भी 1980 के दशक में देश में वित्तीय घाटा बढ़ा, जो 1980 के उतरार्द्ध में सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत रहा। इससे 1990 के दशक के दौरान सार्वजनिक निवेश तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़े।

औद्योगिक दृष्टि से जिया-उज-हक के शासन काल में अर्थव्यवस्था को विनियमित तथा उदारीकृत किया गया ताकि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। दशक में सरकार की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं–कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का विराष्ट्रीयकरण, निजी क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन के पैकेज का प्रावधान तथा विनियामक नियंत्रणों का उदारीकरण आदि रहीं।

इस अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि तथा मध्यवर्ती व मशीन उद्योगों में विकास से पाकिस्तान के उद्योगों का विविधीकरण हुआ।

1980 के दशक में बाजार तथा उत्पादन के विनियमन से पाकिस्तान की कृषि में उल्लेखनीय ढांचागत परिवर्तन आए। कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दृष्टि से लाई गई नीतियों में शामिल थे–चीनी, कीटनाशक तथा उर्वरक उद्योगों का विनियमन, धान एवं कपास निर्यात निगमों के एकाधिकार की समाप्ति तथा निजी क्षेत्र द्वारा खाद्य तेलों के आयात पर लगी रोक को हटाना। कीटनाशकों तथा उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता हटाने से कीमत प्रणाली अधिक बाजारपरक हो गई।

कुल मिलाकर इस अवधि में पर्याप्त समष्टि आर्थिक स्थिरता आई तथा निजी निवेश में फिर से वृद्धि हुई परन्तु बढ़ता हुआ व्यापार तथा बजट घाटा आने वाले समय से अर्थव्यवस्था के शुभ सूचक नहीं थे।

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

दक्षिण एशियाः अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति

दक्षिण एशियाः क्षेत्रीय स्वरूप

दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता-संग्राम 1

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

परिचय

पहले दक्षिण एशिया क्षेत्र को भारतीय उप-महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले पाँच दशकों से यह क्षेत्र 'दक्षिण एशिया' के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख देश हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। इन देशों ने मिलकर सन् 1983 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) का निर्माण किया। कुछ विद्वान, पुराने भारतीय उप-महाद्वीप का हिस्सा होने के कारण अफगानिस्तान तथा बर्मा (म्यांमार) को भी दक्षिण एशिया क्षेत्र का ही देश मानते हैं। सार्क में अफगानिस्तान और म्यांमार को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों देशों को अभी दक्षिण एशिया क्षेत्र का भू-भाग नहीं माना जा सकता है। क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधन की दृष्टि से भारत इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत के एक विशाल देश होने के कारण दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्रों पर इसकी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच अनेकों समानताएं और असमानताएं विद्यमान हैं। नेपाल और भूटान को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राष्ट्र करीब दो सौ साल तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन थे। नेपाल और भूटान ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंग इसलिए नहीं बने क्योंकि ये दोनों देश भी ब्रिटिश सरकार के इशारे पर नाचते रहे। दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख राष्ट्र ग्रामीण और कृषि प्रधान हैं। तेजी से बढ़ती आबादी, निम्न जीवन स्तर और पूँजी का अभाव दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की प्रमुख समस्याएं हैं।

दो सौ वर्षों के अंग्रेजी शासन ने विरासत के रूप में इस क्षेत्र के राष्ट्रों के लिए लगभग एक-सी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं छोड़ी। शिक्षा, कानून, व्यापार, चिकित्सा, औद्योगिक पद्धतियों आदि की दृष्टि से दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में अभूतपूर्व समानता पायी जाती है। भौगोलिक और आर्थिक रूप से इस प्रदेश में परिपूरक तत्त्व विद्यमान हैं, लेकिन इसकी उपेक्षा करके इस क्षेत्र के राष्ट्र एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता में रत हैं। कुछ लोग भारत को दक्षिण एशिया की प्रधान शक्ति (Pre-dominant power) मानते हैं, पर सम्भवतः उसे श्रेष्ठ (Pre-eminent) शक्ति कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान से इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसे अपनी इच्छानुकूल अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर सके। भारत और पाकिस्तान इस प्रदेश के प्रधान प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी देशों ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाने का प्रयत्न किया है। अब तो पाकिस्तान भी निर्गुट आन्दोलन में शामिल हो गया है। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा तथा पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों से सम्बन्धों में इस स्वतंत्रता को बनाये रखने की अभिलाषा इस प्रदेश की सर्वाधिक प्रबल राजनीतिक शक्ति रही है।

भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से समन्वयकारी तत्त्व विद्यमान होने के बावजूद इस क्षेत्र के देशों में सहयोग की इच्छा की अपेक्षा पारस्परिक अविश्वास की भावना अधिक प्रबल है। इस प्रदेश के देशों के पारस्परिक सम्बन्ध अधिकांशतः द्विपक्षीय आधार पर संगठित हुए हैं, बहुपक्षीय आधार पर नहीं। क्षेत्रीय सहयोग का आर्थिक विकास नहीं हुआ है, फिर भी सार्क इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण

www.neerajbooks.com

कदम है। दक्षिण एशियाई देशों के आपसी सम्बन्ध मधुर होते हुए भी विवादों से ग्रस्त रहे हैं। कश्मीर को लेकर भारत-पाक विवाद, तमिल प्रवासियों को लेकर भारत-श्रीलंका विवाद, फरक्का विवाद को लेकर भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहे हैं। अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति और पाकिस्तान को अमेरिकी शस्त्रों की आपूर्ति ने दक्षिण एशिया के द्वार पर नवशीत-युद्ध की दस्तक दी है। आज के बदलते समय में विश्व राजनीति में इन देशों की प्रमुख भूमिका हो गई है। राष्ट्रों के समुदाय में इनकी आवाज का काफी महत्त्व है। जहाँ यूरोप ने हमें दो महायुद्ध दिए, इस क्षेत्र से हमें आशा है कि यह विश्व को स्थायी शान्ति प्रदान करेगा, क्योंकि इस दिशा में इन देशों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। दक्षिण एशिया के देश संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई मंचों पर शान्ति के लिए पैरवी करते रहे हैं। सन् 1947 में दिल्ली में एशियन लिबरेशन्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। इसके पश्चात् सन् 1955 में अफ्रो-एशियन देशों की बांडुंग (इण्डोनेशिया) में कॉन्फ्रेंस हुई। इन सम्मेलनों ने विश्व का ध्यान शान्ति की ओर या एक देश से दूसरे देश की शोषण समस्या पर केन्द्रित करने का प्रयास किया और एक नई एवं न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए आह्वान किया। इससे पूर्व सन् 1954 में, भारत और चीन ने संयुक्त रूप से शान्ति के प्रसिद्ध पाँच सिद्धान्तों, पंचशील का प्रतिपादन किया। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं: अनाक्रमण, समानता एवं पारस्परिक लाभ, एक दूसरे की सम्प्रभुता एवं प्रादेशिक अखण्डता का आदर, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना एवं शान्तिमय सह-अस्तित्व। इस क्षेत्र के किसी भी देश ने यूरोपियन राजनीति के अखाड़े में लड़ी गई किसी लड़ाई में अपने को सम्मिलित नहीं किया।

बोध-प्रश्न–1

प्रश्न 1. भारत में अतिवादी नेताओं द्वारा अपनाए गए राजनीतिक सिद्धांत एवं पद्धतियों की चर्चा करें।

उत्तर–भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि यह अनेक दौर से गुजरा है। कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती दौर में नरमपंथी नेता भारतीय स्वतंत्रता के बदले राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार के पक्ष में थे। इन दिनों आन्दोलन का नेतृत्व दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। लेकिन इन नेताओं की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों की मांग को अनदेखा कर लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व वाली अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के अधिकारों को कम कर दिया। इतना ही नहीं अंग्रेज सरकार ने हिन्दू बहुल पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी बीच बाल गंगाधर तिलक, अरविन्द घोष, लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के नेतृत्व में अतिवादी गुट का गठन हुआ जिसे खाड़कू नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रवादी तत्त्व नरमपंथी दल की विफलताओं को देखते हुए अतिवादी गुट की तरफ बड़ी संख्या में आकृष्ट हुए। इस अतिवादी गुट ने एक नई प्रकार की नीति और संघर्ष के लिए एक नए प्रकार का रास्ता अख्तियार किया। इनके प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे–विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश सरकार से सभी सम्बन्धों का विच्छेद करना, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना तथा स्वदेशी का प्रचार करना। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार से प्रदत्त उपाधियों और पदों का परित्याग तथा परिषदों और विद्यालयों का बहिष्कार भी इनके कार्यक्रमों में शामिल था। इनके इन क्रियाकलापों से पता चलता है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इनका तेवर आक्रामक था। इनका मानना था कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति पर चलकर कभी भी भारत की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। ब्रिटिश सरकार की अर्थ नीति भारत के शोषण पर आधारित है।

अतिवादी गुट की इन नीतियों के कारण इसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। इनकी नीतियों के कारण भारतीय जनता के मन में राष्ट्रीय गौरव, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। इतना ही नहीं अतिवादी गुट ने निम्न मध्यम वर्ग, छात्रों एवं युवाओं के बीच एकता स्थापित की। लेकिन इस आन्दोलन की सिर्फ एक कमजोरी थी और वह यह थी कि यह हिन्दू धारणाओं पर आधारित थी। हिन्दू धारणाओं पर आधारित होने के कारण इनकी धर्मनिरपेक्षता की छवि को धक्का लगा। अतिवादी गुट की इसी नीति के कारण इसे मुसलमानों का विश्वास जीतने में कामयाबी नहीं मिली और मुसलमानों द्वारा मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक विचारधारा को अपनाने के पीछे यह एक बड़ा कारण था।

प्रश्न 2. पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों की मुख्य शिकायतें क्या थीं?

उत्तर–भारत विभाजन के परिणामस्वरूप मुसलमानों ने अपने लिए एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण किया। बंगलादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था। लेकिन पाकिस्तानी शासकों द्वारा वहाँ के बंगालियों के साथ अपनाई गई पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण पृथकतावादी आन्दोलन का जन्म हुआ जिसके परिणामस्वरूप बंगलादेश का एक पृथक राज्य के रूप में जन्म हुआ। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार ने बंगालियों की भावना की कदर न करते हुए उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बना दिया। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना थी, जिससे पाकिस्तान के बंगला भाषियों की आत्मा को ठेस पहुँची और वे पृथक बंगाली राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े हो गए। बंगालियों का कहना था कि ऐसा करके पाकिस्तान सरकार ने उनकी संस्कृति पर कुठाराघात किया है। फिर क्या था, बंगाली समाज और छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलियां तक चलाईं जिसमें कई आन्दोलनकारियों की जानें चली गईं। आन्दोलनकारियों की मौत के कारण बंगाली समुदाय पश्चिमी पाकिस्तान से और भी नाराज हो

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

गया और उनका आन्दोलन उग्र हो उठा। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से दंडित करना शुरू कर दिया।

बंगाली समुदाय अब प्रांतीय स्वायत्तता की मांग करने लगे। यूं तो कहने के लिए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग एक ही देश के नागरिक थे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की नीति पूर्वी पाकिस्तान के संदर्भ में उस क्षेत्र के शोषण पर आधारित थी। पूर्वी पाकिस्तान के पिछड़ापन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सभी आर्थिक स्रोतों और विदेशी मुद्राओं का रुख पश्चिमी पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ उद्योग लगाए भी गए थे उसका लाभ पूर्वी पाकिस्तान को न मिलकर पश्चिमी पाकिस्तान को मिल रहा था, क्योंकि इन उद्योगों के मालिक पश्चिमी पाकिस्तान में ही रहते थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान का दर्जा नीचा था। केन्द्र में पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता स्थापित हो जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नेताओं की उपेक्षा की गई। उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पाकिस्तान के शासकों ने तत्कालीन बंगाल के गैर-बंगाली नवाबों और मुस्लिम व्यापारियों की मदद से पूर्वी पाकिस्तान के मामले को दबाने की कोशिश की। सरकारी कार्यालयों और सेना में भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उचित भागीदारी नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का केन्द्र सरकार पर कब्जा होने के कारण इन्हें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी।

सन् 1954 के आम चुनावों पर भाषाई-आन्दोलन का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। सन् 1949 में भाषाई मुद्दे पर गठित आवामी मुस्लिम लीग ने सभी बंगाली पार्टियों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण कर लिया। अब इन पार्टियों ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता, बंगला को राजभाषा बनाने तथा अन्य कुछ महत्त्वपूर्ण माँगें की। इसका व्यापक प्रभाव पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की लोकप्रियता पर पड़ा। भाषाई मुद्दे पर गठित मुस्लिम लीग चुनावों में हार गई और संयुक्त दलों की सरकार बनी। लेकिन मुस्लिम लीग ने छह माह के भीतर ही संयुक्त सरकार को बर्खास्त कर राज्यपाल शासन के नाम पर सैनिक शासन लागू कर दिया। जब सन् 1959 में जनरल अयूब खान का फौजी शासन प्रारम्भ हुआ तब पूर्वी पाकिस्तान का आन्दोलन शिथिल पड़ गया।

सन् 1954 में बंगलादेश में हुए आम चुनावों पर भाषा-आन्दोलन का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला। यह चुनाव सीमित मताधिकार के अंतर्गत कराया गया था। इस भाषाई-आन्दोलन का दीर्घकालीन प्रभाव देखने को मिला। इसके साथ ही मध्यम वर्गों और अभिजात वर्गों को सत्ता में नहीं आने देना अयूब खान की फौजी तानाशाही शासन का प्रमुख उद्देश्य था। जिन राजनीतिज्ञों का व्यापक जनाधार था, उन्हें अयोग्य करार दिया गया। औद्योगिक एवं व्यापारी वर्गों का सत्ता पर प्रभुत्व कायम कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभेद उभरकर सामने आए। सन् 1966 में जब आवामी लीग के नेता मुजीबुर्रहमान ने एक छह-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की, तब उसमें यह बात खुलकर सामने आई। उन्होंने संघीय और संसदीय प्रकृति की सरकार की स्थापना की मांग की जिसके सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार कर वयस्क मताधिकार के द्वारा हो। उनकी यह भी माँग थी कि केन्द्र सरकार के पास सिर्फ विदेशी और रक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषय ही रहें तथा अन्य विषय प्रान्तीय सरकार के अधीन हों। प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी पृथक मुद्रा तथा पृथक वित्तीय खाते होने चाहिए। इतना ही नहीं प्रत्येक इकाई को अपनी नागरिक सेना और संसदीय शक्तियों को बढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1970 में हुए प्रथम आम चुनाव को हम संघर्ष के तीसरे दौर के रूप में देख सकते हैं। इस चुनाव में आवामी लीग को व्यापक जन समर्थन मिलने के कारण राष्ट्रीय विधान सभा में उसे बहुमत प्राप्त हो गया। अब मुजीब के छह-सूत्रीय कार्यक्रम को प्रस्तावित संविधान सभा से मान्यता मिलना तय था। अतः सत्तारूढ़ सैनिक वर्ग द्वारा राष्ट्रीय विधानसभा का गठन स्थगित कर दिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया। मुजीब ने इन क्रियाकलापों के विरोध में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया। लेकिन इसका कोई भी असर पाकिस्तानी शासकों पर नहीं हुआ, बल्कि उल्टे उन्होंने सैनिक कार्रवाई की मदद से इन आन्दोलनों को दबाने का भरसक प्रयास किया।

सैनिक अत्याचार के परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन सशस्त्र संघर्ष में परिणत हो गया। पुलिस आक्रमण ने वीभत्स रूप धारण कर लिया जिसमें हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न शामिल था। इससे सशस्त्र संघर्ष ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया। बंगाली लोगों का भारत में शरणार्थी के रूप में आना शुरू हो गया। हालांकि यह पाकिस्तान का विशुद्ध रूप से निजी मामला था लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी कि भारत भी इससे अपने को अछूता नहीं रख सका। भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों को सभी संभव सहायता यथा भोजन, आवास, प्रशिक्षण आदि प्रदान किया। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अन्ततः पाकिस्तान को इस युद्ध में हार कर बंगलादेश मुक्ति सेना और भारतीय सेना की संयुक्त कमान के सामने घुटने टेकने पड़े और इस प्रकार बंगलादेश का एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ।

प्रश्न 3. सिंहलियों तथा तमिलों के बीच मतभेद कब और किस मुद्दे को लेकर पैदा हुए?

उत्तर–श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। पहले यह देश छोटे-छोटे द्वीप में बंटा हुआ था, जिसका बाद में

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

एकीकरण हुआ। भारत की तरह श्रीलंका भी ब्रिटिश सरकार के अधीन था। श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के मध्य मतभेद मुख्य रूप से सन् 1920 में प्रारम्भ हुए। ब्रिटिश सरकार ने सन् 1920 में एक नए संविधान की घोषणा की। इस समय प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार भयंकर दबाव में थी, जिसके अनेक कारण थे, जैसे–विश्व व्यापार वृद्धि में गिरावट, खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, कामगार वर्गों में असंतुष्टि आदि। सन् 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित संविधान में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों का उल्लेख था–विधानमण्डल में एक निर्वाचित बहुमत, क्षेत्रीय रूप से चुने गए सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी और साम्प्रदायिक प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था। इस प्रकार की नई व्यवस्था से श्रीलंका में एक प्रतिनिधि सरकार तो अस्तित्व में आ गई लेकिन कार्यपालिका गवर्नर और औपचारिक कार्यकारी परिषद् के ही अधीन थी।

इन सुधारों का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव सिंहली और तमिल वर्गों की आपसी समझदारी और सामंजस्य पर पड़ा। एक ओर जहाँ सिंहली नेता साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था समाप्त कर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक तमिल वर्ग साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे ताकि उनके समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यहीं से सिंहलियों और तमिलों के बीच मतभेद शुरू हो गए। तमिलों ने अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में स्थापित कर लिया। एक ओर जहाँ सिंहलियों और तमिलों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस से अपना नाता तोड़कर अपने पृथक संगठन बनाने की तैयारी में जुट गए।

सन् 1931 में श्रीलंका में एक नया संविधान जारी किया गया। इस संविधान ने श्रीलंका के नेताओं को राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। इसका उद्देश्य यह था कि श्रीलंका के नेतावर्ग संभावित स्वशासन की स्थापना के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर सकें। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य परिषद् की व्यवस्था की गई थी जिसमें विधायी और कार्यकारी अंग भी शामिल किए गए थे। विधान परिषद् का गठन इस प्रक्रिया पर आधारित था कि क्षेत्रीय रूप से निर्वाचित सदस्यों की इसमें बहुलता हो। राज्य परिषद् को अन्य कार्यों का संपादन करने के लिए सात समितियों में बाँटा गया था। प्रत्येक समिति का प्रमुख एक मंत्री अथवा अध्यक्ष होता था। इस संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने पहली बार सभी नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया तथा राजनीतिक प्रक्रिया में सभी श्रीलंकाइयों को भागीदार बनाया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन का प्रभाव श्रीलंका की राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक था। इसके प्रभाव से वहाँ का आन्दोलन और भी तेज हो गया। समाज कल्याण के लिए आन्दोलनों में तेजी लाई गई। इसी बीच मार्क्सवादी राजनीतिक दल की स्थापना हुई जिससे कामगार वर्ग के आन्दोलन को प्रेरणा मिली। सार्वभौमिक मताधिकार की शुरूआत से भी धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। बौद्ध पुनरुत्थान एवं सांस्कृतिक विरासत के कारण भी राष्ट्रवाद बँट गया। द्वितीय राज्य परिषद् (1936-47) के बीच इस सार्वभौमिक मताधिकार ने संविधानवादी नेताओं पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे भी राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सम्बन्धी सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की दिशा में अपनी सक्रियता बढ़ाएं।

आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन् 1944 में संवैधानिक समस्याओं के समाधान के लिए सोलबरी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने एक आंतरिक स्वदेशी शासन की स्थापना की सिफारिश की लेकिन इसमें रक्षा और विदेश मामले ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ही रखने की बात कही गई थी। श्रीलंकाई उग्रपंथी तत्त्वों द्वारा सम्पूर्ण आजादी की माँग हो रही थी। इसी बीच भारत स्वतंत्र हो चुका था। अब श्रीलंका के मामले में भी ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनने लगा कि वह 1974 में हुए आम चुनावों में नए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को 4 फरवरी, 1948 के दिन सम्पूर्ण सत्ता सौंप दे। श्रीलंका में शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत ही सहज प्रक्रिया के अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। श्रीलंका में हो रहा अल्पसंख्यक तमिल नृवंशियों का नरसंहार भारत के लिए चिन्ता का विषय रहा है। भारतवंशी तमिलों का भारत से लगाव एवं उनके प्रति भारत का दायित्व तथा इस कारण भारत में उत्पन्न शरणार्थी समस्या के कारण भारत-श्रीलंका मैत्री में कड़वाहट विकसित हुई है। जब तक श्रीलंका में इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वहाँ स्थायी शान्ति की स्थापना संभव नहीं है। कई बार श्रीलंका सरकार और विद्रोहियों के बीच वार्त्ता कर शांति स्थापना के प्रयास किए गए लेकिन अभी तक इस दिशा में सफलता नहीं मिल पाई है।

बोध-प्रश्न–2

प्रश्न 1. नेपाल में राणातंत्र के खत्म हो जाने में किन कारकों का योगदान रहा?

उत्तर–प्राचीन काल में नेपाल छोटे-छोटे रियासतों में बँटा हुआ था। 18वीं शताब्दी में गुरखा रियासत के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल के सभी छोटे-छोटे रियासतों का एकीकरण करके वर्तमान नेपाल देश का निर्माण कर उस पर अपना शासन स्थापित किया और तब से लेकर आज तक नेपाल में शाह वंश के राजाओं का शासन चलता आ रहा है। नेपाल पर कभी भी ब्रिटिश सरकार का कब्जा तो नहीं हुआ लेकिन नेपाल हमेशा ही ब्रिटिश सरकार का एक पिछलग्गु राष्ट्र बनकर रहा और इसीलिए इसकी संप्रभुता

www.neerajbooks.com